फेक न्यूज की मुश्किल

पिछले कुछ सालों में इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के व्यापक विस्तार के साथ फर्जी खबरों, अफवाहों व अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार में भी तेजी आयी है. इस बारे में परंपरागत एवं डिजिटल माध्यमों में लगातार चर्चा और चेतावनी के बावजूद भारत समेत अनेक देशों में यह समस्या गंभीर होती जा रही है. इंटरनेट सोसायटी और संयुक्त राष्ट्र वाणिज्य एवं विकास सम्मेलन के सहयोग से सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन की ओर से कराये गये इपसॉप के सालाना सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि 85 फीसदी लोग फर्जी खबरों के झांसे में आकर उन पर भरोसा कर चुके हैं. यह सर्वेक्षण पिछले साल दिसंबर और इस साल फरवरी के बीच हुआ था तथा इसमें 25 देशों के 25 हजार से अधिक इंटरनेट इस्तेमाल करनेवाले लोगों की राय ली गयी थी. इसमें पाया गया है कि सर्वाधिक फेक न्यूज फेसबुक के जरिये फैलाया जाता है, लेकिन इसके लिए यूट्यूब, ट्विटर और ब्लॉग का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जा रहा है. दिलचस्प है कि सूचनाओं का फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए लोगों ने सबसे ज्यादा दोष अमेरिका, रूस और चीन को दिया है. इस संदर्भ में हमें भारत में इस चुनौती का संज्ञान तत्परता से लेना चाहिए. सरकारी विभागों से लेकर समाचार माध्यमों ने नागरिकों को लगातार चेताया है कि इंटरनेट के रास्ते, खा सकर व्हॉट्सएप से, खतरनाक अफवाहें और गलतबयानी की जाती है. फेसबुक के स्वामित्व के अंतर्गत आनेवाले व्हॉट्सएप का सबसे बड़ा बाजार भारत है, जहां 20 करोड़ से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. अक्सर इस प्लेटफॉर्म का फर्जीवाड़ा फेसबुक पर भी पहुंचता है. फेक न्यूज और अफवाह किस हद तक भयावह हो सकते हैं, इसका उदाहरण 2017 और 2018 में भीड़ द्वारा पीट कर की गयी हत्याओं में देखा जा सकता है. उसका एक स्वरूप राष्ट्रनिर्माताओं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में अभद्र सूचनाओं का आदान-प्रदान है. इपसॉप के सर्वे में ऐसे कई अन्य अध्ययनों में इंटरनेट इस्तेमाल करनेवाले लोगों ने अपने डेटा और निजी सूचनाओं की रक्षा पर भी चिंता जतायी है. व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों एवं व्यवहार को प्रभावित करनेवाले फेक न्यूज को रोकने के लिए सरकारें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बड़ी टेक कंपनियां चिंतित भी हैं तथा उन्होंने कुछ ठोस पहलकदमी भी की है, परंतु इंटरनेट की बेहतरी के लिए सक्रिय कई कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों का मानना है कि टेक कंपनियां तत्परता और क्षमता से कार्रवाई नहीं कर रही हैं. फेसबुक और गूगल भले ही खुद को टेक्नोलॉजी कंपनी कह कर फेक न्यूज रोकने की पूरी जवाबदेही लेने में कोताही कर रही हों, पर यह सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है कि वे इन कंपनियों पर कितना दबाव बना पाती हैं? इस संबंध में मीडिया, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों और नागरिकों को भी सचेत रहना चाहिए तथा जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए.

इंटरनेट की बेहतरी के लिए सक्रिय कई कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षणों का मानना है कि टेक कंपनियां समुचित त्वरा और क्षमता से कार्रवाई नहीं कर रही हैं.

स्वास्थ्य, समरसता हेतु अपनाएं योग

एम वेंकैया नायडू
उपराष्ट्रपति
delhi@prabhatkhabar.in

आज 21 जून, 2019 को जब विश्व के 170 से भी अधिक देशों में पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. यह एक ऐसा अवसर है, जब प्राचीन भारत की इस अनमोल देन तथा अमूर्त वैश्विक विरासत के इस अनूठे हिस्से की महत्ता पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए.

योग, जिसे विभिन्न रूपों में पूरे विश्व में अपनाया गया है और जिसकी लोकप्रियता में सतत वृद्धि हो रही है, एक ऐसी पुरातन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्रिया है, जिसका जन्म भारत में संभवतः पांचवीं सदी ईसा पूर्व में हुआ. यह एक प्रभावी व्यायाम ही नहीं, उससे अधिक भी बहुत कुछ है. यह स्वास्थ्य लाभ की एक सम्यक विधि है, जो शरीर एवं मन के मध्य के महत्वपूर्ण संबंध को मान्यता देती है. योग 'संतुलन' एवं 'समभाव,' 'शांति,' 'स्थिर प्रज्ञा' तथा 'सुघड़ता' को लक्षित करता है. यह उत्कृष्टता, संश्लेषण एवं समरसता के संधान की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति तथा भारतीय विश्व-दृष्टि का एक मुखर प्रतिमान है.

योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ 'जुड़ना' या 'जोड़ना' होता है. योग का विज्ञान शरीर एवं मन से शुरू करके मानवीय अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जोड़ता है. भारतीय ऋषियों ने बल देकर शारीरिक स्वास्थ्य को एक स्वर से मानवीय उन्नति का पहला अहम पड़ाव माना है- शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् यानी शरीर ही धर्म का साधन है. यह मानते हुए कि योग स्वास्थ्य एवं खुशहाली का एक संपूर्ण मार्ग है तथा यह भी कि योग साधना के लाभों के विषय में सूचनाओं का व्यापक प्रसार वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने प्रस्ताव संख्या 69/131 के द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी.

हम अप्रत्याशित दिशाओं में अभूतपूर्व परिवर्तनों की महान चुनौतियों के काल में जी रहे हैं. हम जिस तरह जीते, सीखते, काम करते और आनंद लेते हैं, उसमें तेजी से बदलाव हो रहे हैं. प्रौद्योगिकी के जरिये जीवनशैलियों का रूपांतरण हो रहा है. हम आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि के अपने अथक प्रयास में, सुविधा एवं आराम की बढ़ोतरी में, अपनी जानकारी तथा दक्षता की वृद्धि में और मनोरंजन एवं शिक्षा विषयक अपने विकल्पों की व्यापकता में अहम प्रगति हासिल कर रहे हैं, मगर जब वैश्विक समुदाय ने वर्ष 2015 में अपने विकास के एजेंडे का खाका खींचना आरंभ किया, तो उसने यह महसूस किया कि 'विकास' का एक बड़ा हिस्सा हमसे छूट रहा है. तब एक संतुलन की जरूरत महसूस की गयी. गरीबों तथा खुद पृथ्वी का ख्याल रखने की जरूरत थी. 'समग्र राष्ट्रीय उत्पाद' के साथ ही 'समग्र राष्ट्रीय प्रसन्नता' की आवश्यकता अनुभूत की गयी. आत्यंतिकता, प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और अत्यधिक उपभोग से बचने की जरूरत थी. तब सतत वहनीयता (सस्टेनेबिलिटी) नया मंत्र बनी, जिसके केंद्र में 'संतुलन' हो. और योग यह बताता है कि कैसे शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू कर हम सभी क्षेत्रों में संतुलन साध सकते हैं.

योग चिंतन, व्यवहार, सीखने तथा समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका है. यह हमें हमारे बाह्य पर्यावरण से जोड़ने तथा विचार एवं व्यवहार के सकारात्मक समन्वय का एक अनोखा मार्ग है.

प्राचीन भारत की उत्कृष्ट कृति भगवद्गीता की दो महत्वपूर्ण उक्तियां हैं: योगस्थः कुरु कर्माणि (अपने कर्तव्य योग की दृष्टि से करें) तथा समत्वं योग उच्यते (समत्व को ही योग कहते हैं). योग जीवन का ऐसा तरीका है, जो शारीरिक संतुलन, मानसिक समभाव तथा पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न तत्वों के समरस संश्लेषण के लिए कार्य करने पर केंद्रित है. इसलिए यह सर्वथा उचित ही है कि वर्ष 2019 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'जलवायु विषयक क्रियाकलाप' है.

योग के लाभों को धीरे-धीरे पूरे विश्व में समझा जाने लगा है. अब, जबकि विश्व महामारियों के दौर से निकल उस ओर बढ़ रहा है, जहां समग्र रोग भार में गैर-संचारी रोग वर्गों का अनुपात बढ़ता जा रहा है, यह महत्वपूर्ण हो चला है कि मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों का चयन कर जीवनशैली के ऐसे प्रतिमानों का अनुपालन करे, जो उत्तम स्वास्थ्य का पोषण करते हों. जैसा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विशेषज्ञों ने माना है, आसन, श्वास-प्रश्वास, गहरा विश्राम तथा ध्यान जैसे अपने चार अवयवों के साथ योग स्वास्थ्य पर खासा सकारात्मक असर डालता है. चूंकि योग हमारे शरीर की कई प्रणालियों पर एक साथ काम करता है, हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने यह दर्ज किया कि यह प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत करता एवं मधुमेह की दवाओं की जरूरत में 40 प्रतिशत तक की कमी ला देता है. यह सचमुच अत्यंत संतोष का विषय है कि योग के द्वारा भारत पूरी पृथ्वी के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्यवर्धन में अपना योगदान कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ज्ञान के इस भंडार को साझा करने के इस विराट आयोजन का नेतृत्व कर रहे हैं. यह तथ्य कि मोदीजी के नेतृत्व की सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रायोजित इस प्रस्ताव को एक साथ 177 देशों ने सह-प्रायोजित किया, योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता के साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य के समर्थन हेतु भारत की इच्छा का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है.

उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के पश्चात विभिन्न राष्ट्रों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए मैं उन देशों के दौरे करता रहा हूं. मुझे यह देख कर सुखद विस्मय हुआ कि योग पूरे विश्व में अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है. अमेरिका समेत कई देशों के स्कूली पाठ्यक्रमों में योग को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है. योग केवल स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए ही नहीं 'ध्यान' तथा 'उत्कृष्टता' के लिए भी अहम है. जैसा गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम् (कर्म में कुशलता योग है).

इस प्रकार, योग चिंतन, व्यवहार, सीखने तथा समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका है. यह हमें हमारे बाह्य पर्यावरण से जोड़ने तथा विचार एवं व्यवहार के सकारात्मक समन्वय का एक अनोखा मार्ग है. यह स्थिरता लाता है, योग्यता बढ़ाता है एवं मित्रभाव का वर्धन करता है. यह सतत वहनीयता का एक प्रभावी आधार बन सकता है. इस पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं प्राचीन भारत के ऋषियों की इस कालजयी सार्वजनीन प्रार्थना से भारत तथा विश्व के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं: सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् यानी सभी जन सुखी और स्वस्थ हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी सर्वत्र शुभता के दर्शन करें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े. (अनुवाद : विजय नंदन)

बोधि वृक्ष

योग का पथ

रहस्यवाद एक प्रकार से कभी न समाप्त होनेवाला वह प्रयास है, जो असीम और ससीम के मध्य संपर्क का संधान करता है. यह संपर्क संधान एक प्रकार से प्रयत्न की निरंतरता भी है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सूत्रों को खोजने का अंतहीन प्रयास है. खुद और खुदा को जोड़ने का तरीका है. मनुष्य की एषणा कभी भी वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होती. संस्कृत में इसे कहा जाता है- 'नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्', मानवीय तृष्णा कभी सीमित से संतुष्ट नहीं हो सकती, मनुष्य की भूख कभी सीमित वस्तु से तृप्त नहीं हो सकती. अनंत आनंद की खोज में जब मनुष्य ने परमपुरुष की ओर चलना शुरू किया, तब वह अध्यात्म के संपर्क में आया. आध्यात्मिकता जब ससीम के संपर्क में आती है, तब इसी के माध्यम से ससीम भी असीम के संपर्क में आता है. ससीम और असीम का यह मिलन ही 'योग' कहलाता है. असीम को पाने के लिए अपनी असीमित क्षुधा की तृप्ति के लिए साधक जब मिष्टिक शैली में उस अनंत की ओर चलना शुरू करता है, उसे ही योग कहा जाता है. संस्कृत में योग का अर्थ है- जोड़ना. उदाहरणस्वरूप जैसे- दो जोड़ दो बराबर चार, लेकिन मिष्टिक लक्ष्य प्राप्त करनेवाले साधक के लिए, ब्रह्म संप्राप्ति के लक्ष्य को पानेवाले साधक के लिए, 'योग' मात्र इस तरह का जोड़ नहीं है. यहां योग का अर्थ है 'एकीकरण', लेकिन एकीकरण के मामले में चीनी पानी में मिल जाने के बाद अपनी अलग पहचान नहीं रख पाता, क्योंकि चीनी पानी में घुल कर पानी के साथ एकाकार हो गया, यही एकीकरण है. मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में योग का तात्पर्य इसी तरह का एकीकरण हैं, अर्थात वृहद के आकर्षण को लक्ष्य कर चलने की गतिशीलता मनुष्य को परमपुरुष के साथ एकाकार कर देती है, जिनका आसन मानव अस्तित्व के उर्ध्वतम बिंदु के भी ऊपर है. परम तत्व के साथ एकात्म होने के लिए, अणु मन की यह जो गतिधारा है, वृहद के साथ क्षुद्र का यह जो मिलन का प्रयास है, यही है योग का पथ.

श्री श्री आनंदमूर्ति

विदेश नीति का वैचारिक पहलू

तरुण विजय
वरिष्ठ नेता, भाजपा
tarunvijay55555@gmail.com

गत सप्ताह चीन में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अकादमियों में मुझे तीन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनका मुख्य विषय दोनों देशों के मध्य गतिशील सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित था. भारत-चीन संबंध महाभारतकालीन हैं, यह तो प्रमाणित है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी चीन के रेशम का जिक्र है. हजार साल पहले चीन के राजगुरु के नाते भारत के बौद्ध भिक्षु कुमारजीव (चीनी भाषा में चोमोलिशु) प्रतिष्ठित किये गये थे. हर भारतीय दिन में अनेक बार जिस दानेदार शक्कर का इस्तेमाल करता है, वह चीन से ही आयी थी, इसलिए उसे हम चीनी कहते हैं. साल 1962 का अपवाद छोड़ दें, भारत-चीन आध्यात्मिक संबंध हमेशा अच्छे ही रहे हैं. लेकिन, क्या वर्तमान भारत-चीन संबंध उस वैचारिक और सांस्कृतिक विरासत के परिदृश्य में देखे जा सकते हैं?

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंध बराबरी और भारत हित सुरक्षित करने हुए दृढ़ता के आधार पर नये दौर में प्रवेश कर चुके हैं. गत वर्ष वुहान में अनौपचारिक शिखर वार्ता को दोनों देशों के मध्य एक मील का पत्थर माना जाता है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले चीनी राष्ट्रपति हैं, जो किसी विशेष विदेशी मेहमान की अगवानी के लिए राजधानी बीजिंग से बाहर किसी नगर में पहुंचे और गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी की मेहमाननवाजी की. चीन को भारत की बात माननी पड़ी तथा संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने में भारत को सफलता मिली. अन्य विषय भी हैं, जो असहमति के बिंदु हैं, जैसे भारत-चीन व्यापार में भयानक असंतुलन है. सत्तर प्रतिशत से अधिक व्यापार चीन के पक्ष में है. भारत की दवाएं अब भी बड़ी मात्रा में चीन के बाजार में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं. भारत को पेंसिलिन दवाओं तथा इंजेक्शनों की आपूर्ति करनेवाला चीन सबसे बड़ा देश बना, जो इन दवाओं के निर्माण के मूल तत्व भेजता है और जो कारखाने भारत में इनका निर्माण कर रहे थे, वे चीन की अतिशय आपूर्ति के दबाव में बंद हो चुके हैं. इस्पात के क्षेत्र में भी चीन भारत से कच्चा माल यानी लौह अयस्क भारती मात्रा में ले रहा है और उसका भारत के स्टील निर्माण पर खराब असर पड़ा है. दिल्ली की खिलौना दुकानें तथा खिलौना निर्माता या तो सिर्फ चीन का सामान बेच रहे हैं या उनके यहां ताले लग गये हैं. पंचकुइयां रोड और कीर्ति नगर की लक्कड़ मंडियां कभी भारतीय कारीगरों, भारतीय लकड़ी और उनसे निर्मित सामान का देश का बड़ा बाजार हुआ करती थीं, आज वह सब बंद हो चुका है और जो पहले निर्माण के केंद्र हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ चीन से आयातित लकड़ी के फर्नीचर तथा अन्य सजावटी सामानों का व्यापार होता है.

नये भारत में जिन विचारधाराओं का योगदान है, चीन उसे समझे बिना भारत को समझ नहीं सकता. पूंजीवाद और साम्यवाद के सामने एकात्म मानववाद का दर्शन नये भारत की सत्ता नीति का आधारभूत हिस्सा है.

भारत की वर्तमान सरकार यह स्थिति बदलने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है. चीन में ऐसे साम्यवाद का शासन है, जिसके लिए देशभक्ति तथा 'चीन प्रथम' की नीति सर्वोपरि है. भारत के साम्यवादी देशभक्ति को पाप और अपराध मानते हैं तथा उनके लिए विदेश निष्ठा ही राजनीतिक मजहब है. चीन में देशभक्ति बहुत पवित्र और सरकार की आधारभूत निष्ठा का प्रतीक है. वे चीन के प्राचीन सम्राटों एवं बौद्ध संतों का सम्मान के साथ अपने साहित्य में उल्लेख करते हैं. भारत से गये बौद्ध भिक्षु जैसे कुमारजीव, समंतभद्र, मातंग और कश्यप वहां के ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं. चीन बौद्ध मत के संरक्षण और प्रसार के लिए विशेष रुचि दिखा रहा है तथा वहां के सभी बौद्ध मठों में एक पुस्तकालय और शाकाहारी भोजनालय होता ही है.

अब चीन में भारत को नेहरूवादी और वामपंथी चश्मे से देखने के बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा के दर्पण में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है. वहां संघ पर सकारात्मक दृष्टि से एक पुस्तक प्रकाशित करने की भी योजना बन रही है. मुझे कुनमिंग की युन्नान सोशल साइंस अकादमी और सिचुआन विवि में छात्रों व अध्यापकों के समक्ष भारत-चीन सांस्कृतिक संबंधों पर बोलने का अवसर मिला. कुनमिंग में बीसीआइएम अर्थात बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार के मध्य गठबंधन और उसके द्वारा आपसी संपर्क मार्गों और अन्य संबंधों को छूना था, जबकि सिचुआन में विचारधारा का विषय था. वहां के वैचारिक नेताओं में यह जानने की उत्कंठा थी कि मोदी की सफलता के पीछे किस विचारधारा का प्रभाव है. आश्चर्य है कि अब तक चीन के पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं संघ का साहित्य पहुंचना चाहिए था, लेकिन कम ही दिखता है. इसका कारण चीन के वैचारिक क्षेत्र में नेहरूवादी और वामपंथी प्रभाव का प्राबल्य ही कहा जा सकता है.

नये भारत में जिन विचारधाराओं का योगदान है, चीन उसे समझे बिना भारत को समझ नहीं सकता. पूंजीवाद और साम्यवाद के सामने एकात्म मानववाद का दर्शन नये भारत की सत्ता नीति का आधारभूत हिस्सा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय को सर्वोच्च वरीयता दी थी और सामाजिक समता और समरसता एकात्म मानव दर्शन का आधार है. चीन के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत पूंजीवाद और साम्यवाद को अस्वीकार करनेवाली विचारधारा पर चल रहा है, जिसे एकात्म मानव दर्शन कहते हैं. इसके लिए हिंदू जीवन पद्धति या हिंदुत्व सम्मान और गौरव का विषय है. चीन के विद्वानों ने दीनदयाल जी और डॉ मुखर्जी का साहित्य अपने पुस्तकालयों में लाने का आश्वासन दिया.

आपके पत्र

सभी शहीदों को मिले सम्मान

देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे सैनिक, अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान अलग-अलग मोर्चों पर शहीद हो रहे हैं, मगर शहीद का दर्जा सिर्फ सेना के जवानों को प्राप्त हो रहा है, अन्य को नहीं. शहादत तो सभी सुरक्षा बलों की एक जैसी है. सब में समर्पण और त्याग की मिसाल एक जैसी है. फिर यह अंतर क्यों और कैसे? यह अन्याय व अमानवीय है. मोदी सरकार से जनता को आशा है कि वह तुरंत इस भेद को समाप्त कर एक मिसाल कायम करे. यह सच है कि किसी वस्तु या राहत से शहादत को तौला नहीं जा सकता, लेकिन शहीद के प्रति यह बड़ा सम्मान हो है. आशा है सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठायेगी.

वेद मामूरपुर, नरेला

सांसदों का व्यवहार

प्रचंड बहुमत से जीती भाजपा के नवनिर्वाचित सांसदों के व्यवहार का नमूना मंगलवार को उस समय दिखा, जब दर्शक दीर्घा देशी-विदेशी मेहमानों से खचाखच भरी थी. हैदराबाद से 'ऑल इंडिया मजलिस ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) दल के नेता असदुद्दीन ओवैसी शपथ ले रहे थे. उसी दौरान भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद 'जय श्री राम', 'वंदेमातरम्' और 'भारत माता की जय' के नारे जोर-जोर से लगाने लगे. इसकी पुनरावृत्ति बंगाल से आये तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के शपथ ग्रहण के दौरान भी की गयी. इस घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि प्रोटेम स्पीकर के बार-बार मना करने के बावजूद नारे लगने बंद नहीं हुए, जबकि एक दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री ने भी सभी नवनिर्वाचित सांसदों से सदन की गरिमा बनाये रखने की अपील की थी. इस नवनिर्वाचित सांसदों का इस तरह का व्यवहार भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

स्वच्छ रांची के लिए पूरा प्रयास हो

झारखंड राज्य ग्रामीण विकास विभाग, काजू बागान, रांची के मुख्य के द्वार की सड़क नगर निगम का कूड़े संग्रह केंद्र बनी हुई है. इसके ठीक बगल में बगल में रांची के सांसद का निवास स्थान है. वहां कई महत्वपूर्ण कार्यालय एवं शिक्षण संस्थान भी हैं, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. गंदगी का ढेर यहां ऐसे पड़ा रहता है, जैसे यह कोई अहम बात ही न हो. मॉर्निंग व इवनिंग वॉक के लिए अधिकांश लोग अपने बच्चे के साथ यहां आते हैं, क्योंकि यहां आसपास कोई पार्क भी नहीं है. फिर भी न तो नगर निगम को स्वच्छता और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, न ही सरकारी तंत्र को. पेड़ों की कटाई से रांची का वातावरण पहले जैसा तो रहा नहीं, ऊपरी से कूड़े के ढ़ेर और बहु मंजिले भवन यहां के लोगों के स्वास्थ्य एवं जनजीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं. इस ओर सरकार और नगर निगम को ध्यान देना चाहिए. उम्मीद करता हूं कि इस समस्या पर रांची नगर निगम, शहरी विकास से जुड़े लोग और अन्य सरकारी तंत्र अविलंब ध्यान देंगे और इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे.

जितेंद्र चौधरी, रांची

कुछ अलग

मुफ्त हाथ आये तो बुरा क्या है?

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

'मुफ्त' शब्दकोश में ही 'मुफ्त' होता है, व्यवहार में उसकी भी एक कीमत होती है, जो बहुत बड़ी भी हो सकती है. दक्षिण अफ्रीकी राजनेता डेसमंड टूटू ने लिखा है कि जब मिशनरी लोग अफ्रीका आये, तो उनके पास बाइबल थी, जिसे वे मुफ्त में बांट रहे थे, और हमारे पास थी जमीन. उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए मुफ्त में प्रार्थना करने आये हैं. हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोलीं, तो हमारे हाथ में बाइबल थी और उनके हाथ में हमारी जमीन.

अपने देश में मुफ्तखोरी की इस आदत को सबसे पहले चार्वाक ने महिमामंडित किया था, जिन्होंने कहा था कि जब तक जियो, सुख से जियो और कर्जा लेकर ही सही, पर घी पियो. कर्ज लेना भी मुफ्तखोरी का ही एक रूप है, जिसे आम आदमी भले ही वैसा न समझे, बड़े-बड़े उद्योगपति खूब समझते हैं, जो बैंकों से कर्ज लेते ही इसलिए हैं कि चुकाना नहीं है, भले ही विदेश क्यों न भागना पड़े. बैंक भी यह समझते-बूझते हुए उन्हें कर्ज देते हैं कि यह रकम वापस नहीं आयेगी. ऐसे कर्जों के लिए उन्होंने 'एनपीए' नामक दान-खाते की व्यवस्था की हुई है, जिसे हिंदी में 'गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां' कहते हैं. यानी ऐसे कर्ज, जिनसे कोई आमदनी होनी तो दूर, उलटे उन्हें खुद डूब जाना है. ऐसे डुबनशील कर्जों को 'गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां' नाम शायद इसलिए दिया गया है, क्योंकि वे गैरों यानी कर्जदारों के लिए निष्पादक संपत्तियां होती हैं, बैंकों के लिए नहीं.

मिर्जा गालिब भी कर्ज की मय पीते थे, लेकिन समझते थे कि हां, रंग लावेगी हमारी फाका-मस्ती एक दिन. वे जानते भी थे और मानते भी, कि मुफ्तखोरी में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसे बुरा नहीं समझते थे- मैंने माना कि कुछ नहीं 'गालिब', मुफ्त हाथ आये तो बुरा क्या है?

लोगों की मुफ्तखोरी की आदत को दो वर्गों ने खूब पहचाना- एक व्यापारी और दूसरे नेता. हालांकि, कुछ लोग इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं करते, क्योंकि उनकी नजर में नेता भी राजनीति को व्यापार समझकर ही चलते हैं. बहुत-से व्यापारी भी देर-सबेर राजनीति में चले जाते हैं, सो इसी कारण. व्यापारियों और दुकानदारों ने लोगों को 'एक के साथ एक फ्री' और 'फ्री डिलीवरी' जैसे प्रलोभन दिये, तो नेताओं ने मुफ्त चावल, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त आमदनी जैसी योजनाओं से भरमाया. इसी सिलसिले में, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा की पेशकश कर दी है. विपक्षियों द्वारा इसका न तो समर्थन करते बन रहा है, न विरोध करते. बहरहाल, उम्मीद है कि महिलाएं इस मुफ्त योजना का खूब लाभ उठायेंगी और यह नहीं सोचेंगी कि उनसे इसकी क्या कीमत वसूली जायेगी.

वैसे जनता इन फरेबों को खूब समझती है. वह जानती है कि नेता उसे बरगलाने के लिए ही वायदे किया करते हैं. यही कारण है कि वह नेताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती. गालिब की तरह वह भी खुशी से मर न जाती अगर एतबार होता? फर्क सिर्फ यह है कि वह अपनी पसंद के नेता या दल द्वारा ही बरगलाया जाना पसंद करती है.

देश दुनिया से

चीनी प्रशासन ने पहली बार कदम पीछे खींचा

हांगकांग की सबसे बड़ी नेता कैरी लैम ने कहा है कि निजी तौर पर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी. प्रत्यर्पण बिल की वजह से समाज में विवाद, टकराव और बेचैनी पैदा हुई है. लैम ने इसके लिए हांगकांग के लोगों से माफी भी मांगी है. बीते 15 जून को कैरी लैम हांगकांग के लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए विवादों में घिरे प्रत्यर्पण बिल को निलंबित करने का ऐलान कर चुकी थीं. वहां ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जब प्रशासन ने बढ़ाने के बाद कदम पीछे खींचे हों. चीन समर्थित सीइओ ने झुकने का संकेत दिया, फिर भी हांगकां के आम लोग समझौते के मूड में नहीं थे. रविवार (16 जून) को हांगकांग में लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओर जानेवाली सड़कों पर लोगों का हुजूम था. स्टेशन पूरी तरह जाम थे और कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं थी. प्रदर्शनकारी उस बिल की पूरी तरह विदाई चाहते थे, जिसमें ये प्रावधान प्रस्तावित है कि हांगकांग वासियों को मुकदमा चलाने के लिए चीन प्रत्यर्पित किया जा सकता है. सरकार की दलील थी कि सिर्फ गंभीर और आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को ही चीन भेजा जायेगा और हांगकांग के एक जज की मंजूरी के बाद ही प्रत्यर्पण होगा, लेकिन लोग इस बिल को हांगकांग की स्वायत्तता पर हमले के तौर पर देख रहे हैं.

BBC NEWS

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है